दैनिक जागरण

जीवन का प्रत्येक पल नई संभावनाओं के द्वार खोलता है

कश्मीर की लड़ाई

राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं। उन्होंने न केवल यह साफ किया कि लड़ाई कश्मीरियों के खिलाफ नहीं, बल्कि यह भी कहा कि देश के कुछ हिस्सों में कश्मीरी छात्रों के खिलाफ जो घटनाएं हुई हैं वे नहीं होनी चाहिए थीं। वास्तव में कश्मीर की लड़ाई अमन पसंद और भारत समर्थक कश्मीरियों को साथ लेकर ही लड़ी जा सकती है। आज जितनी जरूरत इस बात को सही तरह से समझने की है उतनी ही इसकी भी कि कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ते समय उन तत्वों का प्रतिकार भी करना होगा जो कश्मीरियत की बात करते-करते अलगाव और आतंक की राह पर चल निकले हैं और घाटी के माहौल को विषाक्त करने में लगे हुए हैं। इसी विषाक्त माहौल के चलते एक समय जो कश्मीरियत सूफी परंपरा से पगी और भारतीयता के रंग में रंगी थी वह आज मजहबी कट्टरता में तब्दील हो गई है। कश्मीरियत के दूषित हो जाने के कारण ही वहां सुरक्षा बलों और सेना के खिलाफ पत्थरबाजी होती है और भारतीय हितों को चोट पहुंचाने वाली हरकतें होती हैं। आज अगर कश्मीर में अलगाववाद एक धंधा बन गया है तो यह हुर्रियत कांफ्रेंस जैसे पाकिस्तान परस्त संगठनों के कारण। आखिर पाकिस्तान के इशारे पर काम करने और उसकी ही भाषा बोलने वाले इस तरह के संगठनों से यह उम्मीद की ही क्यों गई कि वे समस्या समाधान में सहायक बन सकते हैं? यह अच्छा नहीं हुआ कि कश्मीरियत को नष्ट-भ्रष्ट करने वाले इन तत्वों को अनावश्यक अहमियत दी गई। इस गलत नीति का नतीजा यह हुआ कि ऐसे तत्व आतंकवाद के खुले समर्थक में तब्दील हो गए।

ऐसा लगता है कि हमारे नीति-नियंताओं ने यह ध्यान ही नहीं रखा कि कश्मीर में किन्हें साथ लेने की जरूरत है और किन्हें खारिज करने एवं हाशिये पर ले जाकर अप्रासंगिक करने की। कम से कम अब तो ऐसी गलतियों से बचा जाना चाहिए। इसी के साथ कश्मीर में असर रखने वाले उन राजनीतिक दलों से भी सावधान रहना चाहिए जो सत्ता में रहते समय अलग सुर में बात करते हैं और विपक्ष में रहते समय अलग सुर में। इस मामले में नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी सरीखे दलों का रुख-रवैया भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। वे कभी हुर्रियत सरीखे संगठनों को साथ लेने की रट लगाते हैं और कभी इस पर जोर देते हैं कि पाकिस्तान से बात तो की ही जानी चाहिए। आखिर जिस देश ने जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर को आतंक की आग में झोंक दिया उससे बात करके क्या हासिल किया जा सकता है? ये राजनीतिक दल और अधिकारों की तो पैरवी करते हैं, लेकिन कश्मीर और शेष भारत के बीच की दूरी घटाने वाली कोई पहल नहीं करते। उलटे ऐसी पहल में बाधक बनते हैं। आज कश्मीर में एक नई शुरुआत करने की जरूरत है ताकि एक ओर जहां अलगाव और आतंक के खुले-छिपे समर्थकों को हतोत्साहित किया जा सके वहीं शांति के समर्थकों को प्रोत्साहित किया जा सके। यह शुरुआत सही सोच वाले कश्मीरियों को भरोसे में लेकर ही हो सकती है।

पुनर्निर्माण पर सवाल

उत्तराखंड में वर्ष 2013 में आई आपदा के भीषण कहर के बाद प्रभावित क्षेत्रों में किए गए पुनर्निर्माण कार्यों पर कैग की रिपोर्ट आंखें खोलने वाली है। ये रिपोर्ट सरकारी तंत्र के साथ ही प्रदेश के राजनीतिक तंत्र और राज्य की गंभीर समस्याओं के समाधान के प्रति उनके रुख पर भी सवाल खड़े करती है। वर्ष 2013 में जल प्रलय के रूप में भीषण त्रासदी के जख्म राज्य शायद ही कभी भूल पाए। उत्तराखंड समेत देश भर के सैकड़ों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा तो संपदा को भारी नुकसान पहुंचा। इस सदमे से उबरने में राज्य को केंद्र सरकार से भी वित्तीय और अन्य जरूरी मदद का सहारा मिला। इस मदद का जिस शिद्दत और सावधानी से पुनर्निर्माण कार्यों में उपयोग होना चाहिए था, वर्षों बीतने के बाद भी नहीं किया जा सका। ये हाल तब है, जब पुनर्निर्माण कार्यों को अंजाम देने वाली सरकारों ने अपनी पीठ खुद ही थपथपाने का कोई भी मौका नहीं चूका। बावजूद इसके हकीकत ये है कि केंद्र से मिलने वाली 2500 करोड़ से ज्यादा इमदाद का इस्तेमाल पांच वर्षों में नहीं किया जा सका। कैग रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है कि पुनर्निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न मदों में दी गई 6259.84 करोड़ रुपये की राशि में से महज 3708.27 करोड़ का ही उपयोग हो पाया। एक ओर राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए केंद्र से ज्यादा धन की मांग करती रही है, दूसरी ओर उपलब्ध केंद्रीय सहायता के बड़े हिस्से का समुचित इस्तेमाल करने में ही राज्य के तंत्र के हाथ-पांव फूल गए। पुनर्निर्माण कार्यों की आड़ में ठेकेदारों पर धन लुटाने का मौका छोड़ा नहीं गया। उत्तराखंड को आपदा से बार-बार गहरे जख्म मिल रहे हैं। ऐसे में तंत्र को इस मामले में जितना संवेदनशील, परिपक्व और राज्य की जरूरतों को लेकर जिम्मेदार होना चाहिए, उसका नितांत अभाव बना हुआ है। अरबों की धनराशि खर्च कर कराए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए पृथक केंद्रीकृत तंत्र की स्थापना नहीं की गई। अब सरकार के लिए बेहतर यही होगा कि कैग की रिपोर्ट से सबक लेकर खामियां दूर करने का गंभीरता से प्रयास करे।

संकट के समय सस्ती राजनीति

संजय गुप्त

एक ओर जहां कांग्रेस को अपने रवैये में सुधार लाने की जरूरत है वहीं उन लोगों को भी जो युद्ध छेड़ने की बात कर लोगों को भड़का रहे हैं

पुलवामा में वीभत्स आतंकी हमले के बाद कुछ दलों और खासकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने जैसी सतही-सस्ती राजनीति करनी शुरू की वह भारतीय राजनीति के गिरते स्तर का नया प्रमाण है। यह गंभीर बात है कि हमारे राजनीतिक दल हर अप्रिय घटना को दलगत राजनीति का विषय बना देते हैं। जब एक दल ऐसा करता है तो फिर उसका जवाब देने की कोशिश में दूसरा दल भी ऐसा ही करता है। इसी के साथ तू तू-मैं मैं की राजनीति जोर पकड़ लेती है। निःसंदेह किसी गंभीर घटना-दुर्घटना के कारणों को लेकर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन जिस मामले में राजनीतिक एकजुटता दिखाने की जरूरत हो उसमें तो छिछली राजनीति का परिचय नहीं दिया जाना चाहिए। क्या इससे खराब बात और कोई हो सकती है कि पुलवामा हमले को लेकर प्रधानमंत्री को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश में कांग्रेस जनता को गुमराह करने से भी संकोच नहीं कर रही? पुलवामा हमले के तत्काल बाद राहुल गांधी ने जिस राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया था उस पर वह चार दिन भी कायम नहीं रह सके। इससे इन्कार नहीं कि पुलवामा हमला सुरक्षा-सतर्कता में चूक को जाहिर करता है, लेकिन आखिर इस चूक को रेखांकित करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से यह बेजा आरोप उछालने का क्या मतलब कि हमले के बाद भी प्रधानमंत्री जिम कार्बेट पार्क में अपने प्रचार के लिए शूटिंग कराने में व्यस्त थे।

समझना कठिन है कि कांग्रेस प्रवक्ता ने तथ्यों को तोड़-मरोड़कर यह क्यों कहा कि पुलवामा हमले के चार घंटे बाद तक प्रधानमंत्री को उसकी फिक्र ही नहीं थी। उनके मिथ्या आरोपों का जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को सामने आना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि करीब चार बजे पुलवामा में आतंकी हमले में जुट गए। उन्होंने रुद्रपुर की स्थगित कर दी गई रैली में भारी भीड़ जुट जाने के कारण उसे फोन से पांच-सात मिनट संबोधित किया और इस दौरान कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की। इसके बाद उन्होंने रामनगर में एक समीक्षा बैठक की और दिल्ली लौटने का फैसला किया। उन्होंने कार से बरेली तक लंबा सफर तय किया और फिर बरेली हवाईअड्डे पर भी एक समीक्षा बैठक की। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के जिम कार्बेट पार्क में जलवायु परिवर्तन पर शूटिंग में हिस्सा लेने पर बेजा सवाल उठाने के साथ सऊदी अरब और भारत की ओर से जारी संयुक्त बयान पर भी तंज कसे। कांग्रेस को तो यह पता होना ही चाहिए कि कूटनीति में ताली दोनों हाथों से बजती है। जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर तंज कसे उसी के कुछ समय बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान का नाम लेकर निंदा की गई। इसके अगले दिन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया। आखिर कांग्रेस किस आधार पर इस नतीजे पर पहुंची कि मोदी सरकार की कूटनीति कमजोर है?

अवधेश राजपूत

यह स्मरण करना आवश्यक है कि उड़ी में हमले के बाद जब सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी तब सारी दुनिया ने भारत का समर्थन किया था, लेकिन तब कांग्रेस और कुछ अन्य दल उसके सुबूत मांग रहे थे। कांग्रेस को यह भी याद होना चाहिए कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान को नियंत्रित करने के लिए वह सब कुछ नहीं किया गया जो आवश्यक था। निःसंदेह एक ओर जहां कांग्रेस को अपने रवैये में सुधार लाने की जरूरत है वहीं उन लोगों को भी जो युद्ध छेड़ने की बात कर लोगों को भड़का रहे हैं। पाकिस्तान से निपटने की जरूरत से इन्कार नहीं, लेकिन कश्मीर घाटी को भी शांत करने की जरूरत है, जहां पिछले तीन दशकों में अलगाववाद और फिर आतंकवाद को पनपने दिया गया। आज वहां लोगों को इसके लिए उकसाया जा रहा कि वे भारतीय सेना के विरुद्ध हथियार उठाएं।

कश्मीर में अलगाववाद की जड़ में ऐतिहासिक भूलें हैं, जो मुख्यतः कांग्रेस ने कीं। इन भूलों की शुरुआत तब हुई थी जब नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के कहने पर जम्मू-कश्मीर के लिए धारा 370 के रूप में संविधान में अलग व्यवस्था करवाई। नेहरू ने यह काम गृहमंत्री सरदार पटेल की राय की अनदेखी कर किया। इसके बाद जब पाकिस्तानी सेना ने कबायली भेष में कश्मीर पर हमला किया तब उसे खदेड़े बगैर युद्ध विराम कर लिया गया। अगर उस समय सरदार पटेल की बात सुनी जाती तो भारतीय सेना समूचे कश्मीर क्षेत्र से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ देती। जब घाटी में आतंकवाद अपना सिर उठा रहा था और कश्मीरी पंडितों का दमन हो रहा था तब भी केंद्र सरकारों ने चुप्पी साधे रहना बेहतर समझा। इससे आतंकी तत्वों को वहां का माहौल और खराब करने में मदद मिली। इसी माहौल में कश्मीरी पंडित वहां से निकलने के लिए बाध्य किए गए। बाद में घाटी के अलगाव और आतंकवाद ने मजहबी रूप धारण कर लिया। खराब बात यह हुई कि घाटी के लोगों को मुख्यधारा में लाने में कश्मीर के राजनीतिक दल नाकाम रहे। नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी जैसे जो दल अलगाववाद की जड़ बनी धारा 370 की पैरवी करने तथा और अधिक अधिकारों की मांग करते रहे उनसे अब ज्यादा उम्मीद इसलिए नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये दल समस्या समाधान में सहायक कम, बाधक अधिक हैं।

मोदी सरकार ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और कश्मीर में उसके हमदर्दों को सही रास्ते पर लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। बात चाहे अलगाववादी नेताओं से सुरक्षा वापस लेने की हो अथवा सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान जाने वाले अतिरिक्त पानी को रोकने की तैयारी या फिर पाकिस्तान को दिए गए सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र के दर्जे को वापस लेने की-इन फैसलों का संदेश यही है कि केंद्र सरकार केवल सख्त कार्रवाई के मूड में है। भारत के सख्त तेवरों को देखते हुए पाकिस्तान अत्यधिक दबाव में है। उसके होश उड़े हुए हैं। उसे यह डर सता रहा है कि भारतीय सेना कहीं उस पर हमला न कर दे। यह समय बताएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक कर गुलाम कश्मीर में चल रहे आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया जाता है अथवा पाकिस्तान की सिर्फ आर्थिक नाकेबंदी की जाती है। जो भी हो, देश इस पर आश्वस्त हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में साहसिक कदम उठाया गया था वैसा ही कोई कड़ा जवाब इस बार भी देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन एक लंबी योजना मांग करते हैं।

यह समझने की जरूरत है कि जब तक कश्मीर के हालात काबू में नहीं किए जाते तब तक पाकिस्तान भारत को तंग करता रहेगा-भले ही हम उसके कितने ही आतंकी उसकी सीमा में घुसकर मार गिराएं। स्पष्ट है कि पाकिस्तान को जवाब देने के साथ ही कुछ ऐसे उपाय जरूरी हैं जिससे घाटी के लोगों की भारतीय संविधान के प्रति आस्था बढ़े और वे खुद का भारतीय मानें, न कि कश्मीरियत की आड़ में भारत से इतर। उनकी मानसिकता बदलने के लिए उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि भारत के लोग और केंद्र सरकार घाटी में अमन-चैन लाने के साथ ही उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह प्रतिबद्धता राजनीतिक स्तर पर भी झलकनी चाहिए और सामाजिक स्तर पर भी।

response@jagran.com

साहित्य का सम्मान पाने के सूत्र

संतोष त्रिवेदी

सम्मान इनसे इतनी बार रूठा है कि ये चाहकर भी सम्मान-वापसी गिरोह में शामिल नहीं हो पा रहे हैं

सम्मान-समिति की पहले से 'फिक्स' बैठक शहर के एक अज्ञात स्थान पर रखी गई। इसका मकसद था कि साहित्य के मोर्चे पर आ रही गिरावट का मसला उठाना। इसके लिए जरूरी था कि इस बात की तफ्तीश की जाए कि किसे उठाने से कितने लोग गिरेंगे। इसके लिए शहर की नामी इनामी संस्था ने लेखकों से खुला आवेदन मांगा था। इसमें 'उठे' और 'गिरे' दोनों टाइप के लेखक अपनी संभावनाएं टटोलने लगे। जो साहित्य में नए-नए घुसे थे, उन्हें लगा कि सब जगह भले अंधेर हो, साहित्य में अभी भी बहुत कुछ बचा है। इसलिए कुछ लोग साहित्य को और कुछ लोग स्वयं को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़े। पिछले साल से भी अधिक आवेदन आए। समिति के ठीक सामने एक बड़ी सी मेज रखी थी, जिसमें समकालीन साहित्य की सभी संभावनाएं पसरी हुई पड़ी थीं।

अब आइए, पहले समिति के अनुभवी सदस्यों से मिलते हैं। अनुभवी इसलिए कि चारों सज्जन 'सम्मानयाफ्ता' हैं। बड़ी विषम परिस्थितियों में भी ये अपने लिए 'सम्मान' निकाल लाए, जब लग रहा था कि गलती से असल लेखक न झपट ले जाए। इन सभी ने साहित्य की और अपने 'सम्मान' की भरपूर रक्षा की। जो महामना ऊंची कुर्सी पर विराजमान हैं, निर्णायक मंडल के अध्यक्ष वही हैं। वह हमेशा हवाई मार्ग से सफर करते हैं। जमीन पर तभी उतरते हैं जब कोई सम्मान लेना हो या देना हो। सरकारें भले बदल जाएं, पर उनका रुतबा नहीं बदलता। जो उनके दाएं बैठे हुए हैं, उन्हें साहित्यिक-यात्राओं का लंबा अनुभव है। शहर के साहित्यिक ठेकों पर उनके नाम का सिक्का चलता है। गोष्ठियां उनके ताप से दहकती हैं। लोग सम्मान के पीछे भागते हैं, सम्मान उनके आगे। साहित्य का कोई ऐसा सम्मान नहीं बचा जो उनकी निगाह से न गुजरा हो। लोग जैसे अपनी जिंदगी में बसंत देखते हैं, साहित्य में वैसे वह 'सम्मान' देखते हैं। यहां तक कि लोग उनसे सम्मान पाने के सूत्र तक पूछते हैं।

महामना के ठीक बाएं जो सज्जन दिख रहे हैं, वह बड़े भारी और वजनी रचनाकार हैं। महामना के करीब रहने से भी इनका वजन बढ़ा है। इस बात का इन्हें लेशमात्र भी घमंड नहीं है। ये उनके प्रति समर्पित हैं और साहित्य इनके प्रति। समिति के अभी तक के परिचय से आप कतई आक्रांत न हों। इसमें संतुलन बरकरार रहे इसके लिए भी समुचित उपाय किए गए हैं। मेज के कोने में बैठे सज्जन इसी उपाय का प्रतिफल हैं। कोना हर लिहाज से उनके लिए मुफीद है। वह बैठक से कभी भी बहिर्गमन कर सकते हैं। यह कोना उन्हें इसलिए मुहैया कराया गया है, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल उसके पास है। जो भी वहां बैठे उनका काम बस इतना है कि समिति को वे ईमानदारी से संभावित-सम्मानित की खबर दें, ताकि समिति बहुमत से उस नाम को खारिज कर सके। मेज पर पड़े कागज के टुकड़ों को उठाने से पहले अध्यक्ष जी ने सावधान करते हुए कहा, 'आओ जो भी खाना-पीना है, निर्णय देने से पहले ही कर लें। इससे किसी भी तरह के अपराध-बोध से अपना स्वाद खराब करने की जरूरत नहीं रहेगी।' महामना के इस विनम्र आह्वान के बाद सभी सदस्य मेज पर टूट पड़े। थोड़ी देर बाद जब डकारें कमरे के बाहर जाने लगीं तो बैठक शुरू हुई। महामना ने लिफाफों पर एक नजर डाली और कोने वाले सज्जन से कहा कि वह अपनी संस्तुति पेश करें। उन्होंने कहना शुरू किया, 'जी, यह बड़े हिम्मती लेखक हैं। पिछले तीन सालों से सम्मान की हर दौड़ में हिस्सा लेते हैं, पर आखिरी समय में पता नहीं इनका पत्ता कैसे कट जाता है। सम्मान इनसे इतनी बार रूठा है कि ये चाहकर भी सम्मान-वापसी गिरोह में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अगर यह सम्मान इन्हें मिलता है तो मेरी जिम्मेदारी है कि ये इसे सरकार का विरोध करते हुए वापस कर देंगे। इससे संस्था और लेखक दोनों का नाम होगा।'

तभी महामना के दाएं बैठे सज्जन के जिस्म में जोरदार हरकत हुई। कोने की ओर घूरते हुए बोले, 'देखिए, लेखक को फकीर प्रवृत्ति का होना चाहिए। हमारा वाला पैसे का नहीं सम्मान का भूखा है। मेरी योजना है कि सम्मान का जो भी सामान हो वह लेखक घर ले जाए। रही बात धनराशि की, उसे सम्मान-समारोह संपन्न होने के बाद ही उनसे धरवा लेंगे। गारंटी मैं लेता हूं।' बाएं वाले सज्जन ने प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। महामना ने बहुमत से इसी लेखक को इस साल का 'साहित्यश्री-सम्मान' देने की घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने कोने वाले सज्जन को अगले साल की निर्णायक समिति का सदस्य भी घोषित कर दिया।

response@jagran.com

ऊर्जा

सेवा धर्म

धर्म का सार यही है कि मनुष्य को मनुष्य की सेवा करनी चाहिए। यानी मानव जीवन का उद्देश्य सेवा ही परम धर्म है। सेवा ही असल में मानव जीवन का सौंदर्य और श्रृंगार है। सेवा न केवल मानव जीवन की शोभा, बल्कि परमपिता परमेश्वर की सच्ची अराधना भी है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, गरीबों को धन देना, अनपढ़ को विद्या देना ही हर व्यक्ति का सेवा धर्म है। असल में दूसरों के लिए निःस्वार्थ भाव से किया गया प्रत्येक कार्य सेवा है। यदि हम किसी कामना के लिए दूसरों की सेवा करते हैं, तो वह सेवा नहीं है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमारे मन में असीम शांति की अनुभूति होती है। हम भले ही कितने सुविधा संपन्न क्यों न हों, लेकिन जो सुख हमें दूसरों की सेवा करने से मिलता है, वह सभी सुखों में सर्वोपरि है।

सेवा करने से जो संतोष प्राप्त होता है, वह किसी और कर्म से संभव नहीं है। सेवा भाव से व्यक्ति दूसरों के दुखों को दूर करने की चेष्टा में अपनी परेशानियों को भूल जाता है और उसकी अपनी सामर्थ्य बढ़ जाती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति मानवता की सेवा में जुट जाए तो दुनिया में गरीबी, अशिक्षा, अहंकार, घृणा, पाप और क्रूरता इत्यादि अवगुण स्वतः समाप्त हो जाएंगे और तब सभी सुखी-संपन्न और प्रसन्न हो जाएंगे। असल में, हर देश की भाषा-संस्कृति और बोली अलग-अलग हो सकती है, लेकिन सभी के कल्याण का मार्ग मानवता की सेवा ही है। हम सभी को क्रोध, घृणा, अहंकार को त्यागकर अपने भीतर दया, क्षमा और सेवा का भाव जागृत करना चाहिए ताकि समाज, देश-दुनिया में शांति स्थापित हो सके।

जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि इस लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि दया ही श्रेष्ठ धर्म है। अगर दीन-हीन, असहाय और जरूरतमंद व्यक्ति पर दया दिखाते हुए उनकी सेवा और सहायता नहीं करेंगे, तो कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता है, लेकिन, जब हम एक-दूसरे की सहायता करेंगे, तभी हमारा घर, समाज, देश और विश्व उन्नति की ओर अग्रसर होगा। हमारे वेदों में कहा गया है कि मनुष्य तू दो हाथों से कमा और सैकड़ों हाथों से दान कर। इसी तरह प्रकृति भी हमें यही सीख देती है कि तेरे पास तेरा अपना कुछ नहीं है, जो है वह दूसरों के लिए है।

शंभूनाथ पांडेय

तथ्य-कथ्य

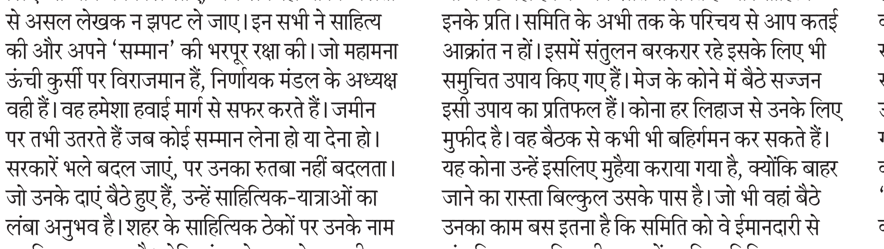

स्रोत: डीजीसीए

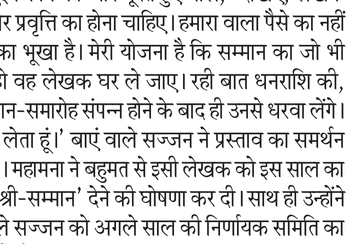

जीवन की भाषा में जुड़े नए अक्षर

मुकुल व्यास

वैज्ञानिकों ने एक डीएनए की दोहरी कुंडलीनुमा आकृति से नया डीएनए बनाया है जिसके गुण जीवन में मददगार हैं

कुछ अरब वर्ष पहले चार मॉलिक्यूल डीएनए की दोहरी कुंडली (डबल हेलिक्स) जैसी आकृति में संगठित हुए। यह डीएनए पृथ्वी पर जीवन की भाषा बना। एक सवाल यह उठता है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए क्या ये चार मॉलिक्यूल ही बुनियादी रूप से आवश्यक थे या दूसरे मॉलिक्यूल्स से भी जीवन का आनुवंशिक कोड बन सकता था? साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन में कहा गया है कि आनुवंशिक कोड में दूसरे मॉलिक्यूल भी सम्मिलित हो सकते थे। वैज्ञानिकों ने अभी हाल में एक डीएनए की दोहरी कुंडलीनुमा आकृति से एक नई किस्म का डीएनए बनाया है जिसके गुण जीवन में मददगार हैं।

वैज्ञानिकों ने चार अतिरिक्त मॉलिक्यूल से कृत्रिम डीएनए की रचना की है। इस तरह जो नया आनुवंशिक कोड बना उसमें चार के स्थान पर आठ अक्षर हैं। अक्षरों की संख्या बढ़ने के बाद इस डीएनए की सूचना भंडारण क्षमता भी बढ़ गई। वैज्ञानिकों ने नए डीएनए का नाम 'हाचीमोची' रखा है। जापानी भाषा के इस शब्द का अर्थ है 'आठ अक्षर।' कुदरती डीएनए में चार मॉलिक्यूल 'नाइट्रोजेनस बेस' भी कहलाते हैं। ये बेस एक-दूसरे के साथ जोड़ा बनाकर पृथ्वी पर जीवन का कोड रचते हैं। 'ए' मॉलिक्यूल 'टी' के साथ जोड़ा बनाता है जबकि 'जी' मॉलिक्यूल 'सी' के साथ जुड़ता है। नए डीएनए में इन चार के अलावा पी, बी, जेड और एस मॉलिक्यूल हैं जिन्हें कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है।

शोधकर्ताओं ने कुदरती और कृत्रिम मॉलिक्यूल के जोड़ों के अनेक मिश्रणों के उपरांत इन हाचीमोची डीएनए की दोहरी कुंडलियां बनाईं। इसके बाद प्रयोग कर देखा कि क्या इन दोहरी कुंडलियों के गुण जीवन में मददगार हैं या नहीं। कुदरती डीएनए में एक बड़ा गुण है जो शायद किसी अन्य आनुवंशिक मॉलिक्यूल में नहीं है। वह यह कि यह स्थिर होता है और इसके आचरण के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि शोधकर्ता सटीक तरीके से यह गणना कर सकते हैं कि विभिन्न तापमानों और अलग-अलग माहौल में यह डीएनए किस तरह से आचरण करेगा। शोधकर्ता हाचीमोची डीएनए के साथ भी ऐसा करने में कामयाब हो गए। उन्होंने कुछ नियम निर्धारित किए जिनके आधार पर डीएनए के स्थायित्व का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। सूचना को संग्रहित करने वाले डीएनए की रचना ही काफी नहीं है।

उसे इस सूचना को आरएनए मॉलिक्यूल में हस्तांतरित करने में भी सक्षम होना चाहिए ताकि आरएनए प्रोटीन को जीव के भीतर काम करने के लिए निर्देश दे सके। हाचीमोची डीएनए की रचना से एक बात साफ है कि यदि ब्रह्मांड में किसी और जगह जीवन को डीएनए में कूटबद्ध किया गया है तो उसकी संरचना पृथ्वी पर पाए जाने वाले डीएनए से भिन्न हो सकती है। शोधकर्ता स्टेवन बेनर का कहना है कि आठ अक्षरों वाला डीएनए का गुच्छा ज्यादा सूचना संग्रहित करने में सक्षम होगा। इसके अलावा इसके और भी उपयोग हो सकते हैं। डीएनए में अक्षरों की संख्या बढ़ा कर डीएनए गुच्छों की विविधता बढ़ी है, लेकिन यह आठ अक्षरों वाले डीएनए का मात्र पहला प्रदर्शन है। संभव है कि हम भविष्य में इससे भी अधिक अक्षरों वाले डीएनए की रचना में सफल हो जाएं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राजरंग

बाबुओं का इंतजार

बदलते मौसम के साथ चुनावी हवाओं की गर्मी का अहसास सियासत ही नहीं नौकरशाही को भी खूब हो रहा है। चुनाव का बिगुल बजने के साथ आचार संहिता लगने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में इन चंद दिनों में सरकार अपनी उपलब्धियां का प्रचार-प्रसार करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसकी वजह से सरकारी बाबुओं पर उपलब्धियों की लिस्ट तैयार करने से लेकर उनकी प्रचार रणनीति और इसे लोगों तक पहुंचाने का दबाव है। इस दबाव की वजह बेहद कम समय में टास्क पूरा करने का ऊपरी आदेश है। इनमें कई बाबुओं के लिए यह दबाव दोहरा है, क्योंकि उनके बच्चे दसवीं या बारहवीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। कई अफसरों ने बच्चों की परीक्षा के लिए पहले से छुट्टी का आवेदन दे रखा था। मगर छुट्टी मिलना तो दूर उन्हें देर रात तक दफ्तर में बैठकर उपलब्धियों की रपट तैयार करने में वक्त बिताना पड़ रहा है। इस कड़ी में कुछ महिला अफसरों को भी बीच-बीच में दफ्तर आना पड़ रहा है जिनकी छुट्टी मंजूर हो गई थी। ऐसे में इस दोहरे दबाव का सामना कर रहे बाबू तेजी से बदलते मौसम की तरह चुनावी आचार संहिता जल्द से जल्द लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे।

पहचान का संकट

पुलवामा आतंकी हमले के मद्देनजर वंदे भारत एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा के दौरान सुरक्षा के इतने कड़े बंदोबस्त किए गए थे कि पत्रकार तो पत्रकार, सरकारी अधिकारियों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। एसपीजी के लोग केवल सूची में शामिल उन लोगों को ट्रेन में सवार होने की अनुमति दे रहे थे जिनके पास पत्र सूचना कार्यालय अथवा रेल मंत्रालय का पहचान पत्र था। रेल मंत्रालय और पत्र सूचना कार्यालय के कुछ अधिकारी इस प्रक्रिया में उनकी सहायता कर रहे थे। सब कुछ ठीक-ठाक ढंग से हो रहा था कि अचानक एसपीजी वाले एक शख्स पर उखड़ गए। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें अधिकारी की अहमियत समझाने का प्रयास किया, लेकिन एसपीजी वाले कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे अधिकारी की पिटाई करते रेलवे के कुछ आला अफसरों ने हस्तक्षेप कर एसपीजी वालों को उनका कार्ड लाकर दे दिया। दरअसल उक्त अधिकारी महोदय जल्दी में अपना पहचान पत्र लाना भूल गए थे और बिना कार्ड के ही अंदर जाने पर अड़े थे। जबकि एसपीजी वाले कह रहे थे कि आप कोई भी हों, हमें उससे मतलब नहीं। बस अपना नाम बताइए और आईकार्ड दिखाइए। चूंकि आपके पास वांछित आईकार्ड नहीं है, लिहाजा आप ट्रेन के अंदर नहीं जा सकते। कुछ पत्रकार इस घटनाक्रम की तुलना उस चुटकुले से कर रहे थे जिसमें राशन की दुकान के मालिक से अनजान जनता उसे बार-बार लाइन से आगे जाता देख पीछे धकेल देती है।

अधूरी सी तैयारी

ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के खराब होने की खबरों और उससे जुड़े सवालों से चुनाव आयोग उबर भी नहीं पाया था कि लोकसभा चुनाव से पहले नवीनतम तकनीक का उपयोग करना उसी पर भारी पड़ने लगा है। आयोग ने चुनाव से पहले मतदाताओं को घर बैठे जो फार्म भरने, चुनाव परिणाम देखने, मतदाता जागरूकता जैसी जो सुविधाएं मोबाइल एप्प से उपलब्ध कराई हैं उनमें आधी से ज्यादा के काम न करने से आयोग हैरान परेशान है। कुछ एप्प और वेबसाइटें तो ऐसी भी है जहां खुद आयोग के अधिकारियों को मुश्किलों का सामना करना पढ़ रहा है। अब ऐसे में वे सभी चुनाव अधिकारी जो कुछ दिनों पहले तक इन एप्प पर गदगद थे और इनका जमकर प्रचार कर रहे थे, आजकल बचते फिर रहे हैं।

चुनाव का असर

जैसे-जैसे आम चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है सरकार के प्रति बाबुओं का लगाव कम होता जा रहा है। सरकारी बाबुओं के साथ-साथ अब सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने नेताओं की फरमाइशों पर ध्यान देना बहुत कम कर दिया है। यह भी अब जरूरी नहीं है कि आज की तारीख में किसी पीएसयू का अधिकारी मंत्री के दफ्तर से आई प्रत्येक सिफारिश पर अमल ही करे। पीएसयू के ज्यादातर अधिकारी इन सिफारिशों को अब नजरअंदाज कर रहे हैं। एक बड़े पीएसयू अधिकारी का कहना है कि इस तरह की सिफारिशों पर अमल अब चुनाव बाद ही होगा। ज्यादातर अधिकारियों का मानना है कि भला अभी नेताओं का काम करके आगे के लिए गर्दन फंसाने की गुंजाइश क्यों छोड़ी जाए?

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।